(c) Government is not aware of any violation of the provisions of Foreign Exchange Regulations Act by the Company.

(d) The amount of excise duty outstanding against the Company is Rs. 4 Crores (approx.) and that of Income Tax is *Nil* at present.

(e) In so far as evasion of excise duty is concerned, all necessary steps including issue of show cause notices, initiation of adjudication proceedings, filing cases in courts of Law have been taken.

नशीले पदार्थों के प्रयोग को रोकने के लिए कानून

@3675-क. **डा० रत्नाकर पांडेय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीले पदार्थों के प्रयोग को रोकने के लिए कुछ नये कानून बनाये जा रहे हैं या वर्तमान कानूनों में संशोधन किया जा रहा है ;

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास के क्षेत्र से नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाली दुकानों को हटाये जाने के लिए की जा रही कार्यवाही में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नशीले पदार्थों की खपत में कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) नशीले औषध-द्रव्यों की बिक्री को विशेषकर शक्षिक संस्थाओं के आसपास इनकी बिक्री को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने हेतु सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिए गये हैं । इस संबंध में उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाही को सुनिश्चित करने हेतु संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पुलिस प्राधिकारियों को उपयुक्त मार्ग-दर्शी सिद्धांत/अनुदेश भी जारी किए गए हैं ।

नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार और नशीले औषध-द्रव्यों के दुरूपयोग को रोकने के लिए समग्र देश में सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालयों में और राज्य पुलिस सगठनों में नार्कोटिक्स कक्षों का भी सृजन किया गया है ।

(ग) नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध पारगमन के दौरान बचे रह गए नशीले औषध द्रव्यों के कारण कुछ स्थानों, विशेषकर, दिल्ली तथा बम्बई जैसे निकासी के स्थानों पर, जहां से इनका अवैध पारगमन होता है, नशीले औषध-द्रव्यों के दुरुपयोग में वृद्धि हुई प्रतीत होती है । तथापि, इस बात का अनुमान लगाना कठिन है कि नशीले औषध द्रव्यों की खपत में किस सीमा तक वृद्धि हुई है ।

Multinationals in India

@@3675-B. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the first twenty-five big multinationals in India;

(b) whether there is any time bound programme given to them for continuing their operations in India or for complete Indianisation of their ownership if so, what are the details thereof; and

(c) whether Government have pursuaded these multinationals to bring modern technologies to India if they want to continue their operations in India; if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) We have not accepted definition of a mul-

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 3233, 25 मार्च, 1988 से स्थानांतरित ।

@@Previously unstarred question 3505, transferred from the 28th March, 1988.